



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934

No. 170]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4, 4 डायमिनी स्टिलबीनी 2, 2 डायसल्फोनिक एसिड (डीएसडीए) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/1/2012-डीजीएडी.—यतः, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार चीन. जन.गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4,4 डायमिनी स्टिलबीनी 2,2 डायसल्फोनिक एसिड (डीएसडीए) (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए मै0 दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, मुम्बई (जिसे एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करने एवं पाटनरोधी उपाय अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

2. और यतः, प्राधिकारी ने यह पाया कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, अतः प्राधिकारी, कथित पाटन एवं उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम -5 में दी गई शर्तों के अनुसार कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी डिग्री तथा उसके प्रभावों का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि जो, यदि अधिरोपित की जाती है, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद 4,4 डायमिनी स्टिलबीनी, 2,2 डायसल्फोनिक एसिड है (जिसे डीएसडीए के रूप में भी जाना जाता है)। इसे 2,2" - (1,2-इथायलीनिडाइल) बीआईएस (5-एमिनोबेन्जीनसल्फोनिक एसिड), 4,4"-डायमिनोस्टिलबीनी-2,2"-डाइसल्फोनिक एसिड, 2,2"-इथीन-1,2-डाइलबिस (5-एमिनोबेन्जीनसल्फोनिक एसिड) अमोनिक एसिड और डीएसडी एसिड के नाम से भी जाना जाता है।

4. डीएसडीए एक हल्के पीले रंग का पाउडर/क्रीम होता है जिसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स फ्लूरोसेन्ट ब्राइटनिंग एजेंट्स आदि जैसे रंग स्टेप्स के सिन्थेसिस में प्रयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्षक 29215990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, हालांकि इसका आयात 29214290 29215990 आदि जैसे कई अन्य टैरिफ शीर्षकों के अंतर्गत भी किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह जाँच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग की स्थिति

5. यह आवेदन मै0 दीपक नाइट्राइट लिमि द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख भाग का उत्पादनकर्ता है जो भारतीय उत्पादन का 90% से अधिक बनता है। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के अलावा मै0 जे.बी. कैमिकल्स, मै0 प्रणव कैमिकल्स और मैसर्स ऐश्वर्या कैमिकल्स भी संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक कंपनी का भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है। अतः, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह आवेदन, उसके अंतर्गत बने नियमों के नियम 5(3) में दी गई शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करता है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समरूप हैं। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम प्रयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों, तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और अतः उन्हें पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत "समान वस्तु" के रूप में माना जाए। इस प्रकार, आवेदक द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तु को इस जाँच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

शामिल देश

7. इस जाँच के शामिल देश चीन जन.गण. है ।

समान मूल्य

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए और आवेदक ने सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुरूप किया है । आवेदक के सामान्य मूल्य का निर्धारण, आवेदक के उपभोक्ता मानदण्डों तथा आवेदक के अनुसार सीमा शुल्क समायोजन के पश्चात अधिप्रापण कीमत के आधार पर करने का प्रस्ताव किया है । आवेदक द्वारा यथानिर्धारित परिवर्तन लागत का दावा किया गया है । नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार यह पूर्वावधारणा की जाती है कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था परिस्थितियों के अंतर्गत प्रचालन कर रहे हैं । उपरोक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था परिकल्पना के मद्देनजर और प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों द्वारा उसके खण्डन के अध्यक्षीन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का आकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में दी गई शर्तों के अनुसार किया गया है ।

निर्यात कीमत

9. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निर्यात कीमत का आकलन आवेदक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना सेवाओं से यथाप्रदत्त कार्यविवरणवार आयात आँकड़ों पर विचार करते हुए किया गया है । निवल निर्यात कीमत पर पहुँचने के लिए समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, हैण्डलिंग प्रभार, वेट समायोजन और पत्तन व्यय के अनुसार कीमत समायोजन की अनुमति दी गई है । पाटनोधी जाँच शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना फैक्टरी बाह्यस्तर पर की गई है जो संबद्ध देश के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन दर्शाता है । इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध वस्तु का संबद्ध देश में सामान्य मूल्य फैक्टरी बाह्य कीमत से अत्यधिक ज्यादा है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है । पाटन मार्जिन का निर्धारण न्यूनतम से अधिक है ।

क्षति और कारणात्मक संबंध

11. आवेदक ने पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन, कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और लाभप्रदायकता, लगाई गई पूँजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह में

कमी के कारण होने वाली "क्षति" के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है। संबद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही "क्षति" के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत पाटनरोधी जाँच शुरू करना न्यायोचित ठहरता है।

जाँच अवधि

12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जाँच अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 (12 माह) थी। तथापि, अधिक अद्यतन आँकड़ों के आधार पर अपक्षित विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी को सक्षम बनाने हेतु, प्राधिकारी एतद्वारा जाँच अवधि 1 जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2012 (15 माह) निर्धारित करते हैं। तथापि क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2008, से मार्च 2009, अप्रैल 2009 से मार्च 2010, अप्रैल 2010 से मार्च 2011 और जाँच की अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत के ज्ञात आयातकों और संबंधित प्रयोक्ताओं एवं घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी अद्योलिखित समय-सीमा के अंतर्गत इस जाँच से संगत जानकारी निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत कर सकता है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)
कमरा सं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-11011

समय सीमा

14. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। ज्ञात आयातक एवं निर्यातक जिन्हें अलग से पत्र भेजा जा रहा है, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पृथक से संबोधित पत्र की तारीख से 40 (चालीस) दिनों के अंतर्गत जानकारी प्रस्तुत कर देंगे। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय-सीमा में विस्तार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों—(क) एक सेट (शीर्षक, विषयसूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) गोपनीय चिह्नित हो और (ख) दूसरा सेट (शीर्षक, विषय-सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) अगोपनीय चिह्नित हो, में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिखा होना चाहिए।

16. ऐसे किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी। गोपनीय तथा अगोपनीय रूपांतर की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

17. गोपनीय मानी गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रस्तुत की गई सूचना के साथ-साथ इस आशय का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता और/अथवा क्यों ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

18. अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए जिसमें उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है के आधार पर गोपनीय सूचना को सूचीबद्ध किया गया हो अथवा उसका स्थान रिक्त रखा गया हो/सारांश दिया गया हो। अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का समुचित अर्थ समझा जा सके। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह उल्लेख कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सारांश न बनाए जा सकने के संतोषजनक कारणों का विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

19. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई सूचना जिसके साथ उसका सार्थक अगोपनीय रूपांतर अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न न हो, को रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के संबंध में अपनी संतुष्टि कर लेने और उसकी आवश्यकता स्वीकारने के बाद ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसे किसी अन्य पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखेंगे। कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग

22. ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2012

Subject : Initiation of Anti-Dumping Duty Investigation concerning imports of 4, 4 Diamini Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA) originating in or exported from China PR.

No. 14/1/2012-DGAD.— Whereas M/s Deepak Nitrite Ltd. (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) alleging dumping of 4, 4 Diamini Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA) (herein after referred to as subject goods), originating in or exported from China PR, for initiation of anti-dumping investigation and for levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating or exported from the subject country.

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from China PR and injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is 4, 4 Diamini Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (also referred to as DASDA). It is also known as 2, 2'- (1, 2- Ethylenediyl) bis (5-aminobenzenesulfonic acid), 4, 4'-Diaminostilbene- 2, 2'-Disulfonic Acid, 2, 2'-ethene-1, 2-diylbis (5-aminobenzenesulfonic acid), Amsonic Acid and DSD Acid.

4. DASDA is a light yellow color powder/cream, which is used in synthesis of dye stuffs, like optical brightening agents, fluorescent brightening agents, etc. The subject goods are classified under chapter heading 29215990, although reportedly being imported under a number of other tariff headings such as 29214290, 29215990 etc. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

DOMESTIC INDUSTRY STANDING

5. The application has been filed by M/s Deepak Nitrite Ltd. on behalf of the domestic industry. As per the evidence available on record, the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods constituting more than 90% of Indian production. Apart from Deepak Nitrite Ltd, M/s J. B. Chemicals, M/s. Pranav Chemicals and M/s. Aishwarya Chemicals are reportedly producers of the subject goods as well. On the basis of available information the Authority notes that the applicant company constitutes a major proportion in Indian production. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

LIKE ARTICLE

6. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are like articles to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

COUNTRY INVOLVED

7. The country involved in the present investigation is People's Republic of China.

NORMAL VALUE

8. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has proposed construction of the normal value on the basis of consumption norms of the applicant and procurement price as per applicant after adjusting for custom duty. Conversion cost has been claimed as incurred by the applicant. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

2795 GE/12-3

EXPORT PRICE

9. Export price of the subject goods from the subject country has been estimated by considering transaction-wise import data as provided by the applicant from International Business Information Services. Price adjustments have been allowed on account of Ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, handling charges, adjustment for VAT and port expenses etc. to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of the export prices of the subject goods from the subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

DUMPING MARGIN

10. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above *de minimis*.

INJURY AND CAUSAL LINK

11. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, price suppression and decline in profitability, return on capital employed, cash flow etc. of the domestic industry. There is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from the subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

PERIOD OF INVESTIGATION

12. The period of investigation (POI) proposed by the applicant was 1st January 2011 to 31st December 2011 (12 months). However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority hereby determines the POI as 1st January 2011 to 31st March 2012 (15 months). The injury investigation period will however cover the periods April 2008-March 2009, April 2009-March 2010, April 2010-March 2011 and the POI.

SUBMISSION OF INFORMATION

13. The known exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi -110011.

TIME LIMIT

14. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

15. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

17. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not

warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

21. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

NON-COOPERATION

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority